ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14
Vol-5, No.-II,PP-1-3, YEAR-Dec.2016

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की भूमिका

❑ विजय सिंह

हमारे समाज का 50 प्रतिशत हिस्सा गंभीर बीमारियों से और 45 प्रतिशत दैनन्दिन मौसमीय या अन्य बीमारियों से ग्रस्त है। यह आंकड़े चौकाने वाले है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज के भौतिकवादी युग में आदमी एक–दूसरे से आगे निकलने और पैसा कमाने की होड में जुटा है और ऐसा वह अपने स्वास्थ्य की कीमत पर करने से नही चूक रहा। षहरों में भौतिकवाद लोगो के स्वास्थ्य को निगल रहा है तो गांवो में निरक्षता, गरीबी और अंधविश्वास के पसरे पावों की बदौलत आम ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

यदि स्वतन्त्रता के पूर्व की बात की जाये, तो उस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग 13 लाख लोग केवल संक्रमण रोगो के कारण काल कवलित हो जाते थे। स्वतन्त्रता के बाद गांवों के स्वास्थ्य परिदृश्य में व्यापक सुधार हुआ है और विविध सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुचाई जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार बालमृत्यु की 50 प्रतिशत घटनाएं केवल 6 देशो–भारत, पाकिस्तान, चीन, कांगों, इथोपिया तथा नाइजीरिया में होती है। भारत के 15 प्रमुख राज्यों में से 10 राज्यो में प्रति एक लाख प्रसव पर माताओं की मृत्युदर 400 से अधिक है। वही गांवो में सभी लोगो को स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने के लिए यूं तो दशियों योजना चालू है लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य ग्रामीण भारत का सपना साकार होने की उम्मीद जागी है। 12 अप्रैल 2005 को स्थापित इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का निस्तार, निगरानी और मुल्यांकन करना है।

आजादी के बाद से सरकार द्वारा अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं लागू की गयी हैं। इन योजनाओं में माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित अनेक योजनाएं चलायी गयी। इनके परिणाम स्वरूप पिछले लगभग छः दशको में देष ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। जैसे– मातृ एवं शिशु–मृत्यु दर में कमी, कई गम्भीर बीमारियों का खात्मा, देशव्यापी टीकाकरण अभियान इत्यादि चलाये गये, लेकिन इन उपलब्धियों के बाद भी देश स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत पीछे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में बहुत सारी विसंगतियां विद्यमान है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बद से बत्तर है, इसके इलावा निजी अस्पतालों की अपेक्षा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित सुविधाओं का अभाव है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाओं के आंकड़े प्रदर्शित होते हैं उनके ग्रामीण अंचलों की हालत खस्ता है। बड़े शहर एवं औद्योगिक शहरों में निजी स्वास्थ्य केन्द्रों की बदौलत ही वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता दिखाई देती है, इस गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग बड़े तबके के लोग ही ले पाते हैं, जो संवेदनशील मुद्दा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण शहरी/ग्रामीण निर्धन परिवारों में रहने वाले लोगों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि दर्ज की जा रही है। जबकि

शोध छात्र, समाज कार्य, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

सरकारी/निजी स्वास्थ्य केन्द्रों की भरमार है लेकिन इन परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी चिकित्सकीय सेवाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध हैं, वर्तमान में इस मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक विस्तार एवं सुधार भी हुआ है। हालांकि जमीनी रूप से देखा जाय तो सरकारी स्वास्थ्य सेवायें आवश्यकताओं के विभिन्न आयामों को सम्बोधित करने में आज भी सुधार की आवश्यकता है। गाँव में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने के लिये यू तो दसियों योजनायें चालू हैं लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के गठन ने स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना साकार होने की उम्मीद जगाया हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उददेश्य :

- आम व्यक्ति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये उत्तम स्तर की उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराना।
- पेयजल, सफाई तथा स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य :

1. शिशु मृत्यु दर में कमी लाना ।
2. मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
3. जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग एवं जनसांख्यिकीय सन्तुलन सुनिश्चित करना।
4. स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण।
5. महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, सफाई तथा स्वच्छता, प्रतिरक्षण और पोषण जैसी जन स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना।
6. एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता।
7. स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं का जीर्णोद्धार करना और आयुश को मुख्यधारा का अंग बनाना।
8. स्वस्थ जीवन शैलियों को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुॅच का आसान बनाने का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर आशा, उपकेन्द्र स्तर पर अनटाइड फण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 24 घण्टे प्रसव एवं नवजात शिशु देखभाल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रथम सन्दर्भण इकाईयों का प्राविधान किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–राज्य में प्रत्येक गांव में (एक हजार की आबादी पर) एक मान्यता प्राप्त महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकत्री का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया है।

"आशा" की कल्पना निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र या ए0एन0एम0 एवं समुदाय के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में की गई है जिसका मुख्य कार्य जन समुदाय में स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना व आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर इलाज कराने की प्रक्रिया में सुविधाकर्ता की भूमिका का निर्वहन करना है। आशा को शासन द्वारा कोई मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि उसके द्वारा किये गये कार्यो के फलस्वरूप धनराशि आवंटित की गयी है।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों जमीनी स्तर पर मिशन के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगी और विभिन्न कार्यकर्ता जैसे ए.एन.एम., आंगनवाडी एवं आशा आदि ग्राम पंचायतों की देखरेख में कार्य करेंगी। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लागू करना एवं इसके उद्देश्यों को प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रामीण, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर पंचायतीराज संस्थायें कितने प्रभाव ढ़ंग से कार्य करती हैं।

मिशन के तहत परिवारों की गर्भवती

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

महिलाओं के प्रसव यदि अस्पतालों में होते हैं तो सरकार की ओर से केवल दो बच्चों तक के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान भी है। तीसरे प्रसव पर यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी यदि मां स्वतः ही परिवार नियोजन के तहत आपरेशन कराए जाने का निर्णय लेती है। योजना का उददे्श्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पंचायती राज संस्थाओं हेतु जिला, ब्लाक एवं गांव स्तरों पर मुख्य भूमिका की परिकल्पना की गई है जिसमें स्वास्थ्य योजना तैयार करना, उस पर नियत्रण एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुपरवाइज करना, आदि शामिल हैं।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. आर.एस., मीणा (2003), 'ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं' कुरूक्षेत्र 48 (7), पृ.सं 43–46
2. कटारिया, सुरेन्द्र (2008), ग्रामीण स्वास्थ्य–गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन, कुरूक्षेत्र–54(12) : पृ.सं. 10।
3. सुखपाल श्रीवास्तव (2008) ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति, कुरूक्षेत्र 54 (12), पृ.30

''उ0प्र0 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पत्रिका (2009)'' प्रजनन एवं बाल्य स्वास्थ्य पुल आउट विशेषांक, प्रकाशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार उ0प्र0 लखनऊ